प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

25.10.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15.00 बजे

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जी एस टी बचत उत्सव ने दीपावली के त्योहार के दौरान मांग, उत्पादन और रोज़गार को बढ़ावा दिया है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। नई दिल्ली से 17वें राष्ट्रीय रोज़गार मेले को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही।

इस बार त्योहारों के इस मौसम में जी एस टी बचत उत्सव ने भी नए रंग भर दिए हैं। यह जी एस टी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा धनतेरस दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है नए–नए रिकॉर्ड बने पुराने रिकॉर्ड टूटे, यह दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। जीएसटी में हालिया सुधारों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुधारों का प्रभाव उपभोक्ता बचत से कहीं आगे जाता है, क्योंकि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार रोज़गार के अवसरों का भी विस्तार कर रहे हैं।

मंत्रिमंडल

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हो रही है। बैठक में शिमला रोप–वे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने सहित जनहित में कई निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

नड्डा–एम्स

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में अब आठ सौ 19 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्नातक चिकित्सा सीटें अब 51 हजार से बढ़कर एक लाख 29 हजार हो गई हैं। आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, नई दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या बढ़कर लगभग 78 हजार हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा विज्ञान, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एम्स ने स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता और रोगियों की देखभाल में अग्रणी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

जीएसटी सुधार

वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी शुरूआत की थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आवास क्षेत्र में नई जीएसटी दरें नागरिकों के लिए मददगार साबित हो रही हैं।

डिस्पैच–

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने विभिन्न निर्माण सामग्रियों में कर कटौती कर इन्हें अधिक किफायती बना दिया है, जिससे आवास और निर्माण क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल रहा है। नए कर ढांचे में मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर जीएसटी दर 12ः से घटकर 5ः कर दी गई है, जिससे फिनिशिंग और फ्लोरिंग की लागत में कमी आई है। इसी प्रकार सीमेंट पर कर की दर को 28ः से घटकर 18ः कर दिया गया है, जिससे निर्माण की कुल लागत में कमी आई है। वहीं, सेंड लाइन ईंटों पर भी जीएसटी को 12ः से घटकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। इन सुधारों से न केवल आवास और बुनियादी ढांचा विकास अधिक किफायती हो रहा है, बल्कि निर्माण क्षेत्र में सतत विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यू–ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली–एन.पी.एस. और एकीकृत पेंशन योजना–यू.पी.एस. के अंतर्गत लाइफ साइकिल–एल.सी. 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल–बी.एल.सी. जैसे निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह कदम उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है, जो चाहते थे कि उन्हें भी निजी क्षेत्र की तरह निवेश के अधिक लचीले विकल्प मिलें। इन विकल्पों का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन बढ़ाना और कर्मचारियों को अपने निवेश को अपनी पसंद और जोखिम क्षमता के अनुसार प्रबंधित करने की आजादी देना है।

लोन

प्राकृतिक आपदा के बीच गंभीर वित्तीय हालात के दौर से गुजर रही राज्य सरकार 200 करोड रूपए का लोन लेगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार कर्ज की यह राशि 6 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी। इसको 29 अक्टूबर 2031 तक लौटाना होगा। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया 28 अक्टूबर को पूरी कर ली जाएगी। सरकारी खाते में यह राशि 29 अक्टूबर को जमा हो जाएगी। दो सौ करोड रूपए का लोन लेने के बाद प्रदेश पर कर्ज की सीमा बढ कर एक लाख एक हजार 7 सौ 75 करोड रूपए हो जाएगी।